



Court Case No -13/2024.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/ATY-1052/JH/39/2023-RO-RNC

श्री चन्द्र शेखर,
सचिव,
राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड सरकार,
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची-834004, झारखंड,
ई-मेल: dolrjh@gmail.com
फोन नं. 2400767, 2400768

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 28.08.2024 को पूर्वाह्न 09:30 बजे, राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. ग्राम-तिकी, पो-जुड़दाग, थाना-करा, जिला-खूँटी, झारखण्ड के मौज़ा तिकी स्थित भूमि विवरण: थाना नं-283, प्लॉट नं-9 के पहान खूट की डालीकटारी भुईहरि जमीन को सर्वे खाता में कायमी दर्ज़ कर पहान खूट के वंशज परिवारों को जमीन से बेदखल करने के संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु श्री विजय युसुफ भेंगरा, ग्राम - चिड़िया, बाजार हाता, पोस्ट-चिड़िया, जिला-पश्चिम सिंहभूम, (झारखंड) से प्राप्त दिनांक 07.01.2020 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 28.04.2023.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 21, अगस्त, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

